पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

श्री संतोष कुमार झा

बनाम

श्रीमती बंदना कुमारी

2015 की विविध अपील सं. 223

20 सितम्बर 2024

(माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(क) और (ख) के तहत क्रूरता और
परित्याग के आधार को स्थापित किया?

हेडनोट्स

अपीलकर्ता द्वारा लिया गया परित्याग (डेज़र्शन) का आधार न तो न्यायसंगत है और न ही विधिसंगत,
क्योंकि यह तथ्य है कि दिनांक 20.05.2011 को उत्तरदाता ने वैवाहिक गृह छोड़ा था और तलाक की
याचिका 05.06.2012 को दायर की गई थी। (अनुच्छेद 17)

परित्याग के आधार पर तलाक हेतु वैधानिक आवश्यक शर्त है कि पति-पत्नी के बीच न्यूनतम दो वर्षों का
पृथक् निवास होना चाहिए, परंतु अपीलकर्ता ने यह याचिका बिना उस वैधानिक अवधि के पूर्ण हुए ही
परित्याग के आधार पर दायर की है। (अनुच्छेद 22)

अभिलेख में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उत्तरदाता ने अपनी इच्छा से
गर्भपात कराया और वह गर्भपात की जिम्मेदार है। एक भी चिकित्सक की गवाही नहीं हुई है

जिससे यह

प्रमाणित हो सके कि उत्तरदाता ने जानबूझकर गर्भपात कराया है। अतः उत्तरदाता की इच्छा से गर्भपात

कराए जाने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। (अनुच्छेद 22)

अपीलकर्ता ने स्वयं अपनी पत्नी को पृथक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कोई सकारात्मक दृष्टिकोण

नहीं दिखाया है। (अनुच्छेद 23)

अपीलकर्ता ने अपनी नाबालिग पुत्री से भेंट (विज़िटेशन राइट) सुनिश्चित करने के संबंध में भी कोई

सकारात्मक प्रयास नहीं किया है। (अनुच्छेद 23)

पत्नी/ उत्तरदाता ने बिना किसी संकोच के यह स्पष्ट रूप से कहा कि वह पति/अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक

जीवन पुनः प्रारंभ करने के लिए तैयार है और इच्छुक है, ताकि एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत किया

जा सके — यह क्रूरता का कोई आधार नहीं हो सकता। (अनुच्छेद 23)

अपील निरस्त की जाती है। (अनुच्छेद 26)

न्याय दृष्टान्त

समर घोष बनाम जया घोष, **(2007) 4 एससीसी 511**; श्री राकेश रमन बनाम श्रीमती कविता, **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 497**; के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा, **(2013) 5 एससीसी 226** वी. भगत बनाम डी. भगत, **(1994) 1 एससीसी 337**; शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी, **(1988) 1 एससीसी 105**; बिपिनचंद्र जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती, एआईआर **1957 एससी 176**; लछमन उत्तमचंद किरपालानी बनाम मीना, **एआईआर 1964 एससी 40**; देबानंद तमुली बनाम काकुमोनी काटाकी, **(2022) 5 एससीसी 459;**अध्यात्म भट्टार अल्वर बनाम अध्यात्म भट्टार श्री देवी, **एआईआर 2002 एससी 88**

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; धारा 13(1)(क) – क्रूरता ; धारा 13(1)(ख) – परित्याग ; धारा 9 – वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक; क्रूरता ;परित्याग ; हिंदू विवाह अधिनियम ; मानसिक पीड़ा ; वैवाहिक कर्तव्य ;वैवाहिक अधिकार ;

संतान से भेंट का अधिकार ;परोक्ष परित्याग ।;साक्ष्य का भार

प्रकरण से उत्पन्न

मूल पारिवारिक न्यायालय, दरभंगा के प्रधान न्यायाधीश द्वारा 19.05.2015 को पारित निर्णय एवं 27.05.2015 के डिक्री के विरुद्ध अपील,वैवाहिक मामला संख्या .73 of 2013 / एच.एम.ए संख्या. 253 of

2012 में।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: सुश्री शमा सिन्हा, अधिवक्ता

प्रत्युत्तरकर्ता की ओर से: श्री समीर रंजन, अधिवक्ता

हेडनोट्स के लेखक: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की विविध अपील संख्या-223

==========

श्री संतोष कुमार झा, पिता - श्री विनोदानन्द झा आयु- 42 वर्ष, निवासी - 51/2, ब्लॉक-ए,इन्द्रप्रकाश कॉलोनी, बुराड़ी, दिल्ली।

.....अपीलार्थी

बनाम

श्रीमति बंदना कुमार, पति- श्री संतोष कुमार झा, पिता- हरिकेश झा, निवासी - राय साहेब पोखर, श्रम कार्यालय लहेरिया सराय, दरभंगा

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी के लिए : श्री सामा सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : श्री समीर रंजन, अधिवक्ता

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडेय

सी.ए.वी. निर्णय

(प्रति :माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडेय)

दिनांक: 20.08.2024

वर्तमान अपील 2013 के वैवाहिक मामला संख्या 73/2013

के एच. एम. ए. संख्या 253/2012 में माननीय विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा द्वारा पारित दिनांक 19.05.2015 के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 27.05.2015 के डिग्री के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत और जिसके अंतर उत्तरदाता के साथ विवाह भंग करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर वैवाहिक मामले को खारिज कर दिया गया है।

2. यह उल्लेख करने योग्य है कि शुरू में, वैवाहिक मामला पारिवारिक न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली के समक्ष दायर किया गया था, लेकिन उत्तरदाता की याचिका पर इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा को दिनांक- 11.02.2013 को 2012 का (दीवानी) संख्या- 1453 के परीक्षण और शीघ्र निपटाने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था।

3. अपीलार्थी के मामले के संक्षिप्त रूप से बताए गए तथ्य यह है कि दोनों पक्षों ने हिन्दू रीति-रिवाजों और संस्कारों के अनुसार दरभंगा में 19.11.2023 को विवाह किया। यह अनुमान लगाया जाता है कि 17.11.2024 को दरभंगा में उपरोक्त विवाह से एक लड़की का जन्म हुआ था। अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया जाता है कि उत्तरदाता एक महत्वाकांक्षी महिला है क्योंकि उसका अपने पिता, जो ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय, दरभंगा में प्रोफेसर हैं, के साथ लगाव है और उत्तरदाता ने यह साबित करने की कोशिश की कि अपने पिता की वो आदर्श संतान है और विवाह की शुरुआत की तारीख से ही , उत्तरदाता ने

कठोर और अडिग दृष्टिकोण दिखाया है और अपीलार्थी के प्रति उसका समझौता न करने वाला रवैया है। अपीलार्थी ने कहा है कि उसने केवल उत्तरदाता के परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण ही रिश्ता जोड़ा था लेकिन उत्तरदाता ने अपीलार्थी का समर्थन नहीं किया क्योंकि वह अपीलार्थी की तुलना में अपने पिता और माता की देखभाल को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया जाता है कि अपीलार्थी उत्तरदाता को अप्रैल 2004 में दिल्ली ले आए लेकिन जुलाई 2004 में उसके पिता आये और उसे वापस दरभंगा ले गए। अपीलार्थी द्वारा आगे यह दावा किया जाता है कि उत्तरदाता जुलाई, 2004 से जनवरी, 2008 तक अपने वैवाहिक घर लौटने के लिए सहमत नहीं थी और उक्त अवधि के दौरान वह दिल्ली घर पे नहीं आयी और अपीलार्थी को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी, 2008 के महीने में उत्तरदाता इस शर्त पर दिल्ली आयी था कि अपीलार्थी उत्तरदाता के लिए एक अलग आवास बनाएगा और उत्तरदाता वैवाहिक घर आ गयी और जुलाई, 2008 तक अपीलार्थी के साथ रही और वह गर्भवती हो गई। जुलाई, 2008 में उसके पिता उसे उसके माता-पिता के घर ले गए और उत्तरदाता की गर्भावस्था को अपीलार्थी की जानकारी के बिना समाप्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि उत्तरदाता को जनवरी, 2009 के महीने में दिल्ली वापस ले गया था और वह फिर से गर्भवती हो गयी और वह अपीलार्थी के इच्छा के विरुद्ध मई, 2009 कुछ परीक्षाओं में बैठने के

बहाने दरभंगा आ गई और फिर से अपीलार्थी को कोई सूचना दिए बिना उसकी गर्भवस्था का गर्भपात करा दिया गया और उत्तरदाता के उक्त आचरण ने अपीलार्थी को सदमा और मानसिक पीरा पहुचाई । अपीलार्थी द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि सितंबर 2010 के महीने में, अपीलार्थी एक दुर्घटना का शिकार हो गया और वह अलग रहा था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, लेकिन वह उत्तरदाता अपीलार्थी द्वारा मानाये जाने के बावजूद अपीलार्थी के साथ में जाने को राजी नहीं हुई । यह भी दावा किया जाता है कि उत्तरदाता जनवरी, 2011 में अपीलार्थी रहने लगी और फिर से गर्भवती हो गयी और उत्तरदाता डॉ. अमिता धवन (स्त्री रोग विशेषज्ञ) के पास नियमित जांच के लिए गई ,जिन्होंने 21.04.2011 को लगभग नौ सप्ताह की गर्भावस्था की पुष्टि की। और फिर से अपने माता-पिता से मिलने के बहाने, उत्तरदाता अपने माता-पिता के घर गई और 20.05.2011 को दिल्ली छोड़ दी और अपने माता-पिता के घर के पहुंचने के बाद, उत्तरदाता ने अपीलार्थी के इच्छा के खिलाफ अपनी गर्भावस्था का गर्भपात कर दिया। यह आगे दावा किया जाता है कि अपीलार्थी दरभंगा पहुंचा, जो अपीलार्थी का मूल स्थान भी है और उसने उत्तरदाता से उसके माता-पिता के घर पर संपर्क किया, लेकिन उत्तरदाता ने अपीलार्थी के साथ रहने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया और वह अपीलार्थी के साथ नहीं गई, जबकि उसके लिए वापसी रेलवे टिकट की व्यवस्था की गई थी । अपीलार्थी द्वारा किए गए अनुनय के बावजूद, सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। यह दावा किया

जाता है उत्तरदाता अपीलार्थी को छोड़ने के लिए दृढ़ है और यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाता का रवैया स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह अपने पति के वैवाहिक घर में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह अपने माता-पिता के घर में ही रह रही है। यह दावा किया गया है कि उत्तरदाता के क्रूर और उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने अपीलार्थी को मानसिक पीड़ा दी है और उनके इस रवैये ने रिश्तेदारों और दोस्तों की नजरों में अपीलार्थी को अपमानित किया है। यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी ने उत्तरदाता की क्रूरता और परित्याग के कृत्य को माफ़ नहीं किया है और उत्तरदाता द्वारा लगातार उत्पीड़न को अत्यधिक मानसिक क्रूरता के अधीन कर दिया है ,जिसके कारण अपीलार्थी के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए ।

4 . नोटिस के अनुसार , दोनों पक्ष उपस्थित हुए और माननीय न्यायलय ने दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते की कोशिश की पर वोअसफल रही।

5. उत्तरदाता ने लिखित बयान दायर किया था। उन्होंने शादी के साथ-साथ एक लड़की के जन्म के तथ्य को स्वीकार किया और अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इन्कार किया। उसने कहा है कि उत्तरदाता गर्भवती थी और महिला डॉक्टर के इलाज चल रहा था और उसे पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन अपीलार्थी ने उसे दिल्ली में गृह प्रवेश में भाग लेने के लिए मजबूर किया और डॉक्टर के सलाह को नजरअंदाज करते हुए करते हुए उसने गृह

प्रवेश में भाग लिया। उसने कहा कि गंभीर स्थिति के दौरान उत्तरदाता को अपीलार्थी-पति सहित उसके ससुराल वालों द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के कपड़े धोने के बाद ताना मारने सहित सभी घरेलु काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उत्तरदाता को दरभंगा में उसके माता-पिता के घर वापस लाया गया जहां उसने डॉ. शैल कुमारी के क्लीनीक में 17.11.2004 को एक लड़की को जन्म दिया क्योंकि दरभंगा में पहले वाली (उपरोक्त में)डॉक्टर उपलब्ध नहीं थी और बच्चे का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ था और सारी लागत उत्तरदाता के पिता ने चुकाई थी। 17.11.2004 को बालिका के जन्म को छोड़कर, अपीलार्थी के दूसरे कथन को उत्तरदाता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। उत्तरदाता द्वारा ये दवा किया गया कि उत्तरदाता ने दिल्ली में अपनी पढ़ाई जारी रखने पर जोर दिया, लेकिन अपीलार्थी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसने उसके आगे के अध्ययन को रोकने के लिए दवाब डालना शुरू कर दिया और उत्तरदाता व्यवहार परिवर्तन को समझ नहीं सकी और वह अपीलार्थी के साथ रहती रही। गर्भावस्था के दौरान वह दरभंगा में अपने माता-पिता के घर आई थी। उत्तरदाता ने आगे दावा किया है कि दिल्ली के संत नगर में घर खरीदने के बावजूद, अपीलार्थी ने अपना आवास नहीं बदला और दिल्ली की इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी में स्थित घर में रहा और अपीलार्थी और उत्तरदाता के निवास के संबंध में पैरा-3 में दिये गए बयान ये इनकार नहीं किया गया है। उत्तरदाता ने कहा है कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्य ने

उत्तरदाता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उत्तरदाता ने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के व्यवहार में बदलाव की उम्मीद के साथ कुछ महीनों तक ऐसा दयनीय जीवन बिताया और उत्तरदाता ने अपीलार्थी से अनुरोध किया कि वह उत्तरदाता को बच्चे के साथ उसके माता-पिता के घर छोड़ दे, जब व्यवहार में कोई बदलाव नहीं देखा गया और उत्तरदाता को अपीलार्थी के परिवार में नौकरानी के रूप में रहने की धमकी दी गई और उसे उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया गया और उसने अपने बच्चे को उचित अध्ययन के लिए स्थानीय पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी, उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप और दवाब के कारण, उत्तरदाता का पिता ने यह देखेते हुए कि ब्राह्मण परिवार पें पुनर्विवाह की कोई परंपरा नहीं है, उत्तरदाता और उसके बच्चे को दिल्ली जाने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गए। नतीजतन, उत्तरदाता और उसका बच्चा दिल्ली स्थानांतरित हो गए। 2009 से उत्तरदाता को अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा और उसने बेहतर भविष्य के लिए सभी व्यवहार को सहन किया। यह कहा गया है कि दरभंगा में रहने की अवधि के दौरान, पूरा खर्च उत्तरदाता के पिता के द्वारा वहन किया गया था और अपीलार्थी ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था और अपीलार्थी ने उत्तरदाता और उसके पिता को धमकी दी थी कि वे उत्तरदाता के बच्चे के साथ दिल्ली जाने दें, अन्यथा अपीलार्थी तलाक का मामला लाएगा और तब उत्तरदाता को

जनवरी, 2011 में उसके बच्चे के साथ वापस लाया गया और अपीलार्थी के साथ खुशहाल वैवाहिक जीवन स्थापित किया और उत्तरदाता फरवरी, 2011 के महीने में फिर से गर्भवती हो गई और डॉ. अमिता धवन सहदेव ने दिनांक 23.04.2011 को उसकी जांच की। और उत्तरदाता की गर्भावस्था की पुष्टि की गई और दवाएं निर्धारित की गई और पूर्ण आराम करने का सुझाव दिया गया। न तो अपीलार्थी और न ही परिवार के सदस्य ने चिकित्सा सहायता प्रदान की, बल्कि उन्होंने उत्तरदाता को कड़ी घरेलू मेहनत करने के लिए मजबूर किया, जिसकी समापन नई दिल्ली में गर्भपात में हुई। उत्तरदाता ने कहा कि अपीलकर्ता उत्तरदाता के साथ संबंध तोड़ने का इरादा रखता है,किसी न किसी बहाने से या जैसा कि अपीलार्थी एक अधिवक्ता है और उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया है कि तलाक याचिका में अपीलार्थी द्वारा किया गया कथन पूरी तरह से गलत और मनगंढ़त है, सिवाय लिखित बयान में स्वीकार किए जाने के।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिग्री कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी गलत है क्योंकि यह धारणाओं, अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि संबंधित अदालत ने इस तथ्य की सराहना नहीं करने में कानून की गंभीर त्रुटि की है कि अप्रैल 2004 से मई 2011 के बीच उत्तरदाता कुछ अंतराल के बाद तीन बार अपीलार्थी के साथ रही और तीनों बार दिल्ली में रहने के दौरान, वह गर्भवती हुई, लेकिन हर बार जब वह अपीलार्थी की इच्छा के खिलाफ

दरभंगा लौटी और वहां अपनी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया और जानबूझकर किये गए गर्भपात ने अपीलार्थी के पूरी तरह से तोड़ दिया है। अपीलार्थी सितंबर, 2010 में एक दुर्घटना का शिकार हो गया, लेकिन उत्तरदाता अपीलार्थी के साथ रहने नहीं आयी , जिससे अपीलार्थी को सदमा और मानसिक पीड़ा हुई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि मई, 2011 में उत्तरदाता ने बिना किसी कारण के वैवाहिक घर छोड़ दिया और उसका कभी भी अपने पति के साथ रहने का इरादा नहीं था और परिवार न्यायालय का निष्कर्ष गलत, विकृत है और इसको दरकिनार किया जा सकता है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने (2007) 4 एस. सी. सी. 511 मामले में रिपोर्ट किए गए **समर घोष बनाम जया घोष** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक पति या पत्नी को बिना किसी कारण के सह-निवास करने से एकतरफा इन्कार करना मानसिक क्रूरता है। क्रूरता के मुद्दे पर ,विद्वान अधिवक्ता ने श्री **राकेश रमन बनाम श्रीमति कविता** 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 497 में रिपोर्ट किया गए मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक और फैसले का भी हवाला दिया है जोकि **के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा** ने (2013) 5 एस. सी. सी. 226 में रिपोर्ट किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक पति या पत्नी द्वारा

दूसरे के खिलाफ झूठे आरोप और मानहानिकारक ब्यान मानसिक क्रूरता के बराबर हैं। विद्वान अधिवक्ता ने (1994)1 एस. सी. सी. 337 में रिपोर्ट किए गए **वी. भगत बनाम डी. भगत** के निर्णय का भी हवाला दिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आधारहीन आरोप मानसिक क्रूरता का गठन करते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने **शोभा रानी बनाम मधुखर रेड्डी** (1988) 1 एस. सी. सी., 105 में अभिलिखित के फैसले का भी हवाला दिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि क्षमा सशर्त है और यदि क्रूरता के कार्य जारी रहते है, तो प्रारंभिक क्षमा स्वतः रद्द कर दी जाती है।

8. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने क्रूरता के आधार पर मामला बनाया है। उसने प्रस्तुत किया है कि परित्याग के आधार पर दबाव नहीं डाला गया है, इसलिए परित्याग के आधार पर तालाक लेने का कोई कारण नहीं है और वर्तमान वैवाहिक मामला परित्याग के मुद्दे पर नहीं है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा की अदालत में भी इस पर जोर नहीं दिया गया है।

9. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 धारा 13 (1) (आई. ए.) और (आई. बी.) के तहत विवाह के विघटन के लिए याचिका दायर की है, जैसा कि तलाक देने के लिए अब तक संशोधित किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि तलाक याचिका के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि

अपीलार्थी ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की है, लेकिन अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि वर्तमान तलाक याचिका में परित्याग तलाक का आधार नहीं है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान उसी आधार पर जोर नहीं दिया गया है। तलाक की याचिका काफी अस्पष्ट है और अपीलार्थी द्वारा निर्दिष्ट कोई विशिष्ट तिथि, समय और स्थान नहीं है जो क्रूरता का स्थापित करता है। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि जब वह सितंबर, 2010 में एक दुर्घटना का शिकार हुआ था, तो उत्तरदाता उसके साथ उसकी परेशानी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन आरोप केवल अनुमानों पर आधारित है क्योंकि उसके इलाज के बारे में कोई दस्तावेज पारिवारिक अदालत में पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने विशेष रूप से एक विशिष्ट तिथि का उल्लेख किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 20.05.2011 पर उसने बिना किसी कारण के वैवाहिक घर छोड़ दिया और तब से वह अपीलार्थी में नहीं रहने पर अडिग थी। उक्त तिथि को छोड़कर, अपीलार्थी ने किसी भी एकल परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है जो समय, स्थान और घटना के संबंध में क्रूरता को स्थापित करती है और यहां तक कि विशेष तिथि यानी 20.05.2011 को लगाए गए आरोप का भी उल्लेख नहीं किया है, जो कि केवल एक निराधार ब्यान है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताता हो कि अपीलार्थी ने प्रयास किए हैं और उक्त प्रयासों का उत्तरदाता-पत्नी द्वारा जवाब नहीं दिया

गया है, बल्कि अपीलार्थी ने उत्तरदाता को अपने पिता के घर पर छोड़ दिया है। उन्होंने आग्र प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने लिखित तर्क प्रस्तुत किया है जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उत्तरदाता ने इस शर्त पर बहुत अनुनय के बाद दिल्ली गयी कि उसकी इच्छा के अनुसार दो कमरों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन साक्ष्य के दौरान अपीलार्थी ने शिकायत में दिए गए निराधार ब्यान के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि लिखित ब्यान के प्रत्युत्तर में अपीलार्थी ने केवल शिकायत के संस्करण को दोहराया है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसने परित्याग के आधार पर जोर नहीं दिया हैं, लेकिन तलाक की याचिका भी परित्याग के आधार पर दायर की जाती है। अपीलार्थी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आई. बी.) के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक वैधानिक अवधि को पार नहीं किया है और अपीलार्थी के अधिवक्ता ने चतुराई से एक याचिका दायर की है कि निचली अदालत में बहस के दौरान परित्याग का आधार पर जोर नहीं दिया गया है। वैधानिक अवधि को, जिम्मेदारी से भागकर या परित्याग के आधार को दबाकर नहीं पार किया जा सकता है। अपीलार्थी-पति दावे के अनुसार, उत्तरदाता ने मई, 2011 में वैवाहिक घर छोड़ दिया है और 05.06.2012 को तलाक की याचिका दायर की गई है, उस आधार पर, परित्यागके आधार पर तलाक लेने के उद्देश्य से वैधानिक अवधि समपप्त नहीं हुई है। अपीलार्थी ने स्वयं दावा किया है कि तलाक की शिकायत में किए गए दावे के शब्दशः अनुसार उत्तरदाता वर्ष 2008 से

2011 के बीच वैवाहिक गृह में शामिल हुआ है। मई, 2011 को छोड़कर, जो कि अपीलार्थी का एकतरफा बयान है और जिसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है ये है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए हैं। उत्तरदाता अपने पति के साथ शामिल होने के लिए तैयार है क्योंकि लिखित ब्यान और उत्तरदाता और उसके पिता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से इसका पता चलात है। इस तरह, अपीलार्थी ने स्वयं उत्तरदाता के खिलाफ क्रूरता के आरोप को साबित नहीं किया है। यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि उत्तरदाता दिल्ली के वैवाहिक गृह में रही ,इसके बजाय अपीलार्थी ने अपनी पत्नी और बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी से बचते हुए उत्तरदाता को अपने पिता के घर पर छोड़ दिया। शिकायत में लगाया गया आरोप केवल एक अस्पष्ट और निराधार ब्यान है जिसका क्रूरता के आरोप को साबित करने का कोई आधार नहीं है।

10. अपीलार्थी की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई है। अ.सा.-(अपीलार्थी गवाह) 1/संतोष कुमार झा स्वयं अपीलार्थी हैं, अ.सा.-2/संजय कुमार झा अपीलार्थी के भाई हैं और अ.सा.-3 बच्चाजी ठाकुर हैं। अपीलार्थी ने कुछ दस्तावेजों पर भी भरोसा किया है जो इस प्रकार हैः-

प्रदर्श 1. स्थानांतरण याचिका सं. 1453, 2012

प्रदर्श 2 आर. टी. आई. उत्तर दिनांक 30.07.2012

प्रदर्श 3. डॉ. अमिता धवन सहदेव द्वारा दिनांकित 16.10.2013 जारी किया गया प्रमाण पत्र।

उत्तरदाता के तरफ से दो गवाहों से पूछताछ की गई है।

वि. सा.- (उत्तरदाता गवाह) 1/बंदना कुमारी स्वयं उत्तरदाता हैं और वि. सा.-2/ऋषिकेष झा उत्तरदाता के पिता हैं। उत्तरदाता ने उत्तरदाता का अल्ट्रा साउण्ड की रिपोर्ट पर भरोसा किया है जो शर्मा दिनांक 31.07.2008 अल्ट्रासोनोग्राफिक सर्विसेज में की गई थी, जो की एक्स अ कके रूप में चिह्नित किया गया है।

11. मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, सवाल उठता हैः

क्या अपीलार्थी ने दिए गए साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आलोक में क्रूरता के साथ-साथ परित्याग के आधार पर मामला साबित किया है या नहीं ?

12. अ.सा.-1/संतोष कुमार झा, जो स्वयं अपीलार्थी हैं, द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है। अपने साक्ष्य में, उन्होंने याचिका के तथ्य पर जोर दिया है और जांच के दौरान उन्होंने कहा है कि लड़की का जन्म 17.11.2004 को हुआ था और उत्तरदाता ने अपने पिता के प्रति झुकाव के कारण वैवाहिक दायित्व को पूरा नहीं किया है। अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि उत्तरदाता ने जानबूझकर उपेक्षा की और अपीलार्थी के साथ न रहने के इरादे से अंत में 20.05.2011 को अपीलार्थी को छोड़ दिया और 2008 से

2011 के बीच की अवधि के दौरान उत्तरदाता तीन बार गर्भवती हो गई और उसने अपीलार्थी की सहमति के बिना अपनी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया।

13. अ.सा.-1/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों पक्षों ने मई, 2011 तक वैवाहिक जीवन फिर से शुरू कर दिया क्योंकि यह अपीलार्थी के दलील के साथ-साथ मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य में भी स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी ने स्वयं निवेदन किया है कि उत्तरदाता इस शर्त पर दिल्ली आया था कि अपीलार्थी एक अलग स्थान पर रहने की व्यवश्ता करेगा , लेकिन अपीलार्थी के उक्त अभिवाचन को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का क्रम के दौरान स्थान नहीं मिला हैं। अपीलार्थी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि दोनों पक्ष मई, 2011 तक वैवाहिक जीवन में शामिल हुए और उपरोक्त विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ और मई, 2011 से उत्तरदाता अपने वैवाहिक घर नहीं लौटी । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को वापस लाने का कोई प्रयास किया है, हालांकि, अपने अभिवचन में उसने जोर देकर कहा है कि उसने अपनी पत्नी / उत्तरदाता को वापस लेने के लिए दिल्ली के लिए वापसी टिकट की व्यवस्था की हे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है कि अपीलार्थी/पति ने अपनी पत्नी को वैवाहिक घर ले जाने की व्यवस्था की है और यहां तक कि उसने अपनी नाबालिग बेटी के लिए मिलने का अधिकार भी नहीं मांगा है जो उत्तरदाता के पोषण में हैं।

14. अ.सा.-2 और अ.सा.-3 ने भी अ.सा.-1 के संस्करण को दोहराया है।

15. वि. सा.-1 स्वयं उत्त्रदाता है। उन्होंने विवाह और एक कन्या के जन्म के तथ्य को दोहराया है जो उत्तरदाता की देखभाल और संरक्षण में रहती थी। उसने आगे कहा कि अपीलार्थी गर्भावस्था के दौरान उसे अकेला छोड़कर दिल्ली चला गया था । उसने इस संस्करण को दोहराया है कि वह अपने वैवाहिक घर में शामिल हुई थी। उसने कहा है कि 2011 में वह गर्भवती हुई और उस पर घरेलू काम के लिए दबाव डाला गया। जिसके परिणामस्वरूप उसका गर्भपात हो गया। उसने कहा है कि न तो उसे और न ही उसकी बेटी को अपीलार्थी द्वारा रखा जा रहा था और वह पूरी वरह से अपने माता-पिता पर निर्भर थी और अपीलार्थी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसने कहा है कि अपीलार्थी उत्तरदाता की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था और उसे अपने पिता के घर पर छोड़ दिया। उसने कहा है कि वह दिल्ली जाती थी, बल्कि अपीलकर्ता ने उसे दरभंगा में छोड़ दिया था। उन्होंने अपीलार्थी द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। उसने इस बात से इंकार किया है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी।

16. उत्तरदाता गवाह सं.-2 ने उत्तरदाता गवाह सं.-1 के संस्करण को भी दोहराया है। यह विशेष रूप से कहा गया है कि उत्तरदाता पूरी गरिमा के साथ वैवाहिक जीवन जीने के लिए हमेशा तैयार रहती है।

17. अभिलेख के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मांगे गए परित्याग का आधार न तो मान्य है और न ही इस तथ्य के आलोक में टिकाऊ है कि 20.05.2011 पर उत्तरदाता ने वैवाहिक घर छोड़ दिया और तलाक की याचिका 05.06.2012 को दायर की गई थी।

18.परित्याग को साबित करने के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की प्रासंगिक धारा 13 (1) (1-बी) है जो निम्नानुसार है-

13 . तलाक-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह, की याचिका पर विचार किया जा सकता है,जब, पति या पत्नी में से किसी द्वारा प्रस्तुत, तलाक की डिग्री द्वारा इस आधार पर भंग किया जाए कि दूसरा पक्ष -

(i.ब) याचिकाकर्ता को याचिका प्रस्तुत करने से तुरंत पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए छोड़ दिया है।

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा में, ''परित्याग '' पद का अर्थ है याचिकाकर्ता का दूसरे पक्ष द्वारा उचित कारण के बिना और सहमति के बिना या ऐसे पक्ष की इच्छा के खिलाफ विवाह के लिए परित्याग , और इसमें विवाह के लिए दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है, और इसके व्याकरणिक बदलावों और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

19. जब हम परित्याग की पृष्टभूमि का उल्लेख कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि दो प्रकार के परित्याग होते हैंः-

(1) वास्तविक परित्याग और (2) रचनात्मक परित्याग परित्याग के मामले में, इसका निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय के माध्यम से किया जाता है और इसकी व्याख्या की गई कि (जिसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर तलाक की कार्यवाही में ''परित्याग'' कहा जा सकता है)। ''परित्याग '' शब्द माननीय उच्चतम न्यायालय की **बिपिनचंद्र जयसिंह बाई शाह बनाम प्रभावती (ए. आई. आर. 1957) एस. ए. सं. 176** के मामले में विचार किया गया था ,न्यायिक जांच के तहत आया है जोकि **उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीना उर्फ मोटा (ए. आई. आर 1964 एस. सी. 40)** के मामले में प्रयोग किया गया था। **बिपिनचंद्र जयसिंह बाई शाह** (उपरोक्त) में यह कहा गया है यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई जीवनसाथी दूसरे को अस्थायी जुनून की स्थिति में छोड़ देता है, उदाहरण के लिए, स्थायी रूप से सहवास बंद करने का इरादा किए बिना क्रोध या घृणा, तो यह परित्याग के बाराबर नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले निर्णयों में की गई टिप्पणियों को जोड़ते हुए अपना विचार इस प्रकार व्यक्त कियाः-

> *'' ऊपर दिए गये टिप्पणियों को जोड़ते हुए इस न्यायालय का दृष्टिकोण इस प्रकार कहा जा सकता हैः एक याचिकाकर्ता पर भारी दबाव पड़ता है जिसपर , परित्याग के चार आवश्यक शर्तों को साबित करने के लिए जिसके आधार पर तलाक चाहता है, अर्थात्, (1)*

अलगाव का तथ्य, (2) त्याग की इच्छा , (3) उसकी /उसके सहमति का अभाव, और (4) उसके/उसकी आचरण का अभाव जो छोड़ने वाले पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने लिए उचित कारण देता है।''

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले में **देवानंद तमुली बनाम काकुमोनी कटकी** ने (2022) 5 एस. सी. सी. 459 में रिपोर्ट किया पारा 8 पर निम्नानुसार अयोजित किया गयाः-

8. पति और पत्नी के बीच विवाद के कारण हमेशा बहुत जटिल होते हैं। हर वैवाहिक विवाद दूसरे से अलग होता है। पलायन का मामला स्थापित होता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह साक्ष्य के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालने का मामला है।

21. सर्वोच्च न्यायालय **अध्यात्मा भट्टार अलवर बनाम अध्यात्म भट्टार श्री देवी** 2022 एस. सी. 88 के मामले में ,सर्वोच्च न्यायालय ने आकाशवाणी में रिपोर्ट किया ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया हैः-

''खंड इस नियम को निर्धारित करता है कि वैवाहिक अपराध के रूप में परित्याग याचिका की प्रस्तुति से तुरंत पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए होना चाहिए। इस खंड को स्पष्टीकरण के साथ पढ़ना होगा। स्पष्टीकरण ने उत्तरदाता द्वारा याचिका दायर

करने वाले पति या पत्नी की जानबूझकर उपेक्षा को शामिल करने के लिए परित्याग की परिभाषा को व्यापक बना दिया है। इसमें कहा गया है कि वैवाहिक अपराध के रूप में परित्याग उचित कारण के बिना और सहमति के बिना या याचिकाकर्ता की इच्छा के खिलाफ होना चाहिए। स्पष्टीकरण से यह बहुत स्पष्ट है कि विधायिका इस अभिव्यक्ति को एक व्यापक महत्व देने का इरादा रखती है जिसमें विवाह के लिए दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है, इसलिए, जहां तक परित्यक्त पति या पत्नी का संबंध है, परित्याग के अपराध के लिए दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, अर्थात्, (1) अलगाव का तथ्य, और (2) स्थायी रूप से सहवास को समाप्त करनेका इरादा । इसी तरह जहां तक परित्यक्त जीवनसाथी का संबंध है, कोई भी तत्व आवश्यक नहीं हैंः (1) सहमति की अनुपस्थिति, और (2) व्यवहार की अनुपस्थिति जो पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए उचित कारण देती है ताकि

उपरोक्त आवश्यक इरादा बनाया जा सके। तलाक के लिए याचिकाकर्ता क्रमशः दोनों पति-[पत्नी मे उन तत्वों को साबित करने और वैधानिक अवधि के दौरान उनकी निरंतरता का बोझ वहन करता है।

22. अपीलार्थी ने क्रूरता के आधार के अलावा अपनी दलील में परित्याग के आधार पर जोर दिया है। तर्क के दौरान, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा है कि उक्त आधार को पहले नहीं दबाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जब अपीलार्थी ने अपनी दलीलों और अपने साक्ष्य में परित्याग के आधार जोर दिया है तो यह तय कानून है कि कोई भी अभिवाचन से परे नहीं जा सकता है। परित्याग के आधार के लिए वैधानिक आवश्यकता दो साल से कम नहीं है और अपीलार्थी ने दो साल की वैधानिक अवधि के अंतराल के बिना परित्याग के आधार पर वर्तमान मामला दायर किया है। इस तरह, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी किसी न किसी बहाने से तलाक लेने के अपने दृष्टिकोण में बहुत जल्दबाजी करता है। अपीलार्थी का उक्त आधार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में न तो मान्य है और न ही टिकाऊ है। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि दोनों पक्ष किसी न किसी अवसर पर एक साथ रहते थे और मई, 2011 तक वैवाहिक दायित्व को पूरा करते थे, लेकिन अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि उत्तरदाता ने वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के दौरान 2008, 2009 और 2011 में तीन बार गर्भधारण किया और अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चलता है कि उत्तरदाता ने अपनी इच्छा से गर्भपात कराया और वह गर्भपात के

लिए जिम्मेदार है। एक भी डॉक्टर की जांच नहीं की गई है कि गर्भावस्था को स्वयं उत्तरदाता के रूप में समाप्त कर दिया गया है, इसलिए आरोप उत्तरदाता की इच्छा पर गर्भावस्था की समाप्ति पूरी तरह से किसी भी भौतिक जानकारी के बिना है।

23. पति के असहयोगी रवैये को उसके स्वयं के प्रतिपादित तथ्य से देखा जा सकता है कि उसने अभिवचन के दौरान कहा है कि उत्तरदाता ने अपीलार्थी के शामिल होने के लिए पूर्व शर्त रखी है यदि उसे अलग आवास प्रदान किया जाता है, लेकिन निचली अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करते समय, अभिवचन में दिए गए ब्यान के बार में एक शब्द नहीं कही गई है। इस तरह, अपीलार्थी ने स्वयं अपनी पत्नी को अलग आवास प्रदान करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दिखया है। अपीलार्थी ने स्वयं अपने अभिवचन में कहा है कि उसने उत्तरदाता के वैवाहिक घर में आगमन को सुरक्षित करने के लिए टिकट वापस करने की व्यवस्था की है, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी / उत्तरदाता के उसके वैवाहिक घर में आगमन को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था की थी। अपीलार्थी ने अपनी नाबालिग लड़की से मिलने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए अपना सकारात्मक रवैया भी नहीं दिखाया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थी ने परित्याग के आधार को लागू करने के लिए वैधानिक अवधि की प्रतीक्षा किए बिना जल्दबाजी में तलाक याचिका दायर करके अपनी पत्नी और बेटी को बनाए रखने के दायित्व से बचने के लिए अपने कानूनी कौशल का उपयोग किया है। दूसरी ओर, उत्तरदाता ने इस

आरोप का खंडन किया है कि उसने अपने पति को स्थायी रूप से शामिल नहीं होने के इरादे से छोड़ दिया था, बल्कि उसने अपने पति की घर में शामिल नहीं होने के सुझाव का खंडन किया और रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि वह अपने पति के साथ शामिल होने के लिए तैयार है और पहले के अवसर पर भी उत्तरदाता अपीलार्थी की गृह में शामिल हो गया है और उसने कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ा है, बल्कि पति ने उसे बच्चे के साथ दरभंगा में छोड़ दिया है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में साबित नहीं किया है, बल्कि उसने निराधार ब्यान दिया है कि उसने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। यह अपीलार्थी का मामला है कि वर्ष 2008 से 2011 के बीच उत्तरदाता/पत्नी ने दिल्ली का दौरा किया और हर बार अपने प्रवास के दौरान, वह गर्भवती हो गई और पति और पत्नी के बीच संबंध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे वैवाहिक जीवन जी रहे है अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और अपीलार्थी पे आरोप लगाया लेकिन आरोप का कोई अर्थ नहीं है जब उसने स्वयं स्वीकार किया कि उत्तरदाता वैवाहिक जीवन में शामिल हो गया है सामान्य वैवाहिक जीवन के दौरान दोनों ने विवाहित जीवन का आनंद लिया है और जैसा कि अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया है कि क्रूरता का आरोप बिना किसी आधार के है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-पति ने आवेदन दायर करने का भी प्रयास नहीं किया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए और यहां तक कि उसने भी अपने बच्चे की देखभाल नहीं की है क्योंकि उसने

किसी भी भेंट अधिकार की मांग नहीं की है ताकि वह अपने नाबालिग बच्चे को देख सके। अपीलार्थी के अभिवचन और साक्ष्य के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उसने तलाक की कार्यवाही के अनुरूप आरोप लगाने के लिए एक गणनात्मक उपकरण बनाया है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने खुद अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से, यह स्पष्ट है कि पत्नी /उत्तरदाता ने बिना अवरोध के स्पष्ट रूप से किसी अवरोध के स्पष्ट रूप से आनंदमय वैवाहिक जीवन जीने के लिए पति/अपीलार्थी की वैवाहिक कंपनी में फिर शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की जो क्रूरता का आधार नहीं हो सकता है।

24. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने क्रूरता के आधार पर निर्णयों का हवाला दिया, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामलों से पूरी तरह से अलग हैं और उक्त संदर्भित मामले वर्तमान मामले में अपीलार्थी की मदद नहीं करते हैं क्योंकि अपीलार्थी ने स्वयं अपनी पत्नी / उत्तरदाता और बच्चे की देखभाल नहीं की है। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आई. ए.) और (आई. बी.) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह भंग करने के लिए याचिका दायर की है। अपीलार्थी के जल्दबाजी वाले दृष्टिकोण को तब देखा जा सकता है जब उसने परित्याग का आश्रय के लिए पलायन की शरण ली है। तलाक का उद्देश्य जिसमें दो साल की वैधानिक अवधि समाप्त नहीं हुई हो। जब अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह पाया जाता है कि वैधानिक अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो विद्वान अधिवक्ता ने मामलों का हवाला देते हुए क्रूरता के मामले, जैसा कि उद्धृत किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह से अलग हैं

क्योंकि उत्तरदाता अपीलार्थी की साथ में शामिल हो गयी थी , बल्कि अपीलार्थी अपनी पत्नी को वापस लाने में विफल रहा और उसे अपनी बेटी के साथ उसके पिता के घर पर अकेला छोड़ दिया और अपीलार्थी द्वारा अपने अभिवाचन में अनुरोध किया गया प्रयास पूरी तरह से निराधार ब्यान है क्योंकि अपीलार्थी उस प्रयास को साबित करने में विफल रहा है जो उसने लाने के लिए किया है। उसकी पत्नी अपने पिता के घर बेटी के साथ वापस आ गई। अभिवाचन में, अपीलार्थी का आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट है क्योंकि क्रूरता के कार्य को गठित करने के लिए विशिष्ट तिथि और समय के साथ एक एकल परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अभिवाचन के अवलोकन से यह पाया गया है कि अपीलार्थी ने उत्तरदाता/पत्नी के खिलाफ लगाए आरोप में कोई विशिष्ट तिथि, समय और स्थान नहीं बनया है ताकि यह दिखाया जा सके कि उसने क्रूरता का कार्य किया है, बल्कि अपीलार्थी ने बहुत अस्पष्ट ब्यान दिया है कि वर्ष 2008 से 2011 के बीच प्रतिवाद अपीलार्थी के साथ शामिल हो गई और वह तीन बार गर्भवती हुई है और उसने अपीलार्थी की सहमति के बिना अपनी गर्भावस्था का गर्भपात कराया है, लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ नहीं है कि गर्भावस्था थी। उत्तरदाता के कहने पर समाप्त किया गया। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तरदाता वैवाहिक गृह में शामिल हो गया है और उत्तरदाता की अभिवचन से यह स्पष्ट है कि वह अपीलार्थी में शामिल होने के लिए तैयार है और उसने इस बात से इंकार किया है कि उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया है, बल्कि अपीलार्थी ने उसे अपने पिता के घर पर छोड़ दिया है। पति/अपीलार्थी के उपरोक्त कार्य के अलावा, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उसने वैवाहिक विवाद को निपटाने के लिए कोई

प्रयास किया है। यहां तक कि उत्तरदाता की इच्छा के अनुसार अलग आवास के उसके अनुरोध को भी अपीलार्थी के साक्ष्य में कोई जगह नहीं मिलती है। इस तरह, अपीलार्थी का अभिवाचन पूरी तरह से अस्पष्ट है और यह केवल एक निराधार ब्यान है जिसका कोई अधार नहीं है।

25. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क न तो मान्य है और न ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के आलोक में टिकाऊ है।

26. पूर्वगामी कंडिकाओं में की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में, हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है जो विवादित फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देती है। दरभंगा के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने तलाक की मांग करने वाले अपीलार्थी के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

वर्ततान अपील को खारिज कर दिया गया है।

तदनुसार, विवादित निर्णय और डिग्री की पुष्टि की पुष्टि की जाती है ।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडेय, न्यायमूर्ति)

शहजाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।